

भारत सरकार  
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय  
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 271

जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया जाना है

**बीएचईएल में वित्तीय संकट**

**271. एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर:**

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने 877 करोड़ रुपये का घाटा दर्शाया है;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने बीएचईएल में और अधिक घाटे को रोकने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री  
(श्री बाबुल सुप्रियो)**

(क): जी, हां। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को तत्कालीन अस्थायी/अनंतिम प्रकाशित परिणामों के अनुसार वित्त वर्ष 2015-16 के लिए ₹877 करोड़ का निवल घाटा दर्शाया है। तदुपरान्त, 27 मई, 2016 को भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) ने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षा के पश्चात् ₹913 करोड़ का निवल घाटा दर्शाया है।

(ख): वर्ष 2015-16 के दौरान बीएचईएल का निष्पादन मुख्य रूप से कारोबार में निरंतर गिरावट के कारण प्रभावित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप प्रचालन स्तर में कमी आई और विभिन्न ग्राहकों की कई फँसी हुई परियोजनाओं, जिनमें कंपनी ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता के रूप में शामिल है, पर रोक नहीं हटी है।

(ग) और (घ): (i) मामला और आवश्यकता की प्रकृति के आधार पर जब भी अपेक्षित होता है सरकार सलाह/सुझाव देती है जो नीति से संबंधित या विशेष मुद्दे से संबंधित हो सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, बीएचईएल ने रक्षा, रेलवे, जल, सौर और पारंपरिक विद्युत क्षेत्र में भी नए उभरते व्यापारिक अवसरों पर गौर करते हुए विविधिकृत होने का प्रयास किया है।

(ii) सरकार ने बीएचईएल के बोर्ड में दो निदेशक (सरकारी नामिती) की नियुक्ति भी की है जो कंपनी की रणनीतिक दिशाओं का निरीक्षण करने, कार्पोरेट निष्पादन की समीक्षा और मॉनिटरिंग करने, नियामक अनुपालन और कार्पोरेट गवर्नेंस सुनिश्चित करने तथा हितधारकों के हितों की सुरक्षा करने में सक्रिय रूप से योगदान करते हैं। बीएचईएल के मुख्य क्षेत्रों में भारी अनुभव रखने वाले 5 स्वतंत्र निदेशक भी कंपनी के बोर्ड में शामिल किए गए हैं।

(iii) इसके अलावा, बीएचईएल के निष्पादन की समीक्षा भारी उद्योग विभाग द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। भारी उद्योग विभाग नीतिगत पहलों, उपयुक्त अंतर्मंत्रालयी हस्तक्षेपों और समय-समय पर विशिष्ट मुद्दों को उठाकर विकास योजना की प्राप्ति में कंपनी की सहायता भी करता है।